

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2005/ज्येष्ठ 17, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2005/JYAISTHA 17, 1927

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2005

सा.का.नि 376(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“सं. आ. 209”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (1) अनुच्छेद 270 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट, सेवाकर से भिन्न, करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का वह प्रतिशत जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, साढ़े उनतीस प्रतिशत होगा जो राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :—

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.356
अरुणाचल प्रदेश	0.288
असम	3.235
बिहार	11.028
छत्तीसगढ़	2.654
गोवा	0.259
गुजरात	3.569
हरियाणा	1.075

हिमाचल प्रदेश	0.522
जम्मू - कश्मीर	1.297
झारखंड	3.361
कर्नाटक	4.459
केरल	2.665
मध्यप्रदेश	6.711
महाराष्ट्र	4.997
मणिपुर	0.362
मेघालय	0.371
मिजोरम	0.239
नागालैंड	0.263
उड़ीसा	5.161
पंजाब	1.299
राजस्थान	5.609
सिक्किम	0.227
तमिलनाडु	5.305
त्रिपुरा	0.428
उत्तर प्रदेश	19.264
उत्तरांचल	0.939
पश्चिमी बंगाल	7.057

(2) उस सेवाकर के, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर है, शुद्ध आगमों का साढ़े उनतीस प्रतिशत, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.453
अरुणाचल प्रदेश	0.292

असम	3.277
बिहार	11.173
छत्तीसगढ़	2.689
गोवा	0.262
गुजरात	3.616
हरियाणा	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.529
झारखंड	3.405
कर्नाटक	4.518
केरल	2.700
मध्यप्रदेश	6.799
महाराष्ट्र	5.063
मणिपुर	0.367
मेघालय	0.376
मिजोरम	0.242
नागालैंड	0.266
उड़ीसा	5.229
पंजाब	1.316
राजस्थान	5.683
सिक्किम	0.230
तमिलनाडु	5.374
त्रिपुरा	0.433
उत्तर प्रदेश	19.517
उत्तरांचल	0.952
पश्चिमी बंगाल	7.150:

परंतु जहां किसी वर्ष में सेवाकर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्ग्रहणीय हो जाता है वहां जम्मू-कश्मीर सहित प्रत्येक राज्य को पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा।

4. अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट, सेवाकर से भिन्न, करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का एक प्रतिशत जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले किन्तु उस तारीख के अपश्चात् जिससे अतिरिक्त उत्पाद-

शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन कर भाटक व्यवस्था समाप्त हो जाती है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.356
अरुणाचल प्रदेश	0.288
असम	3.235
बिहार	11.028
छत्तीसगढ़	2.654
गोवा	0.259
गुजरात	3.569
हरियाणा	1.075
हिमाचल प्रदेश	0.522
जम्मू - कश्मीर	1.297
झारखंड	3.361
कर्नाटक	4.459
केरल	2.665
मध्यप्रदेश	6.711
महाराष्ट्र	4.997
मणिपुर	0.362
मेघालय	0.371
मिजोरम	0.239
नागालैंड	0.263
उड़ीसा	5.161
पंजाब	1.299
राजस्थान	5.609
सिक्किम	0.227
तमिलनाडु	5.305

त्रिपुरा	0.428
उत्तर प्रदेश	19.264
उत्तरांचल	0.939
पश्चिमी बंगाल	7.057

परंतु ऐसे किसी वर्ष में जहां कोई राज्य अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता है वहां उस राज्य को कोई अंश संदेय नहीं होगा।

5. उस सेवाकर के, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर है, शुद्ध आगमों का एक प्रतिशत, जो 1 अप्रैल, 2005 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2010 से पहले समाप्त होने वाले परंतु उस तारीख के अपश्चात्, जिससे अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन कर भाटक व्यवस्था समाप्त हो जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, राज्यों में निम्नलिखित रूप में संवितरित किया जाएगा :-

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आंध्र प्रदेश	7.453
अरुणाचल प्रदेश	0.292
असम	3.277
बिहार	11.173
छत्तीसगढ़	2.689
गोवा	0.262
गुजरात	3.616
हरियाणा	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.529
झारखंड	3.405
कर्नाटक	4.518
केरल	2.700
मध्यप्रदेश	6.799
महाराष्ट्र	5.063

२-५४/१३४५२५

मणिपुर	0.367
मेघालय	0.376
मिजोरम	0.242
नागालैंड	0.266
उड़ीसा	5.229
पंजाब	1.316
राजस्थान	5.683
सिक्किम	0.230
तमिलनाडु	5.374
त्रिपुरा	0.433
उत्तर प्रदेश	19.517
उत्तरांचल	0.952
पश्चिमी बंगाल	7.150:

परंतु ऐसे किसी वर्ष में जहां कोई राज्य अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत करता है वहां उस राज्य को कोई अंश संदेय नहीं होगा।

परंतु यह और कि जहां किसी वर्ष में जम्मू-कश्मीर राज्य में सेवा कर उद्ग्रहणीय हो गया है वहां जम्मू-कश्मीर राज्य सहित प्रत्येक राज्य को पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा।

6. यदि 2005-10 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में संघ के अधीन कोई कर किसी राज्य में उद्ग्रहणीय नहीं हैं तो उस कर में उस राज्य का अंश शून्य कर दिया जाएगा और संपूर्ण आगम शेष राज्यों में उनके अंश को अनुपाततः समायोजित करते हुए वितरित किया जाएगा।

7. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2000, 1 अप्रैल, 2005 से ही निरसित हो जाएगा।

8. किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चात्पूर्ति वर्ष में वसूलीय होंगी।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(6)/2005-वि. 1]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2005

G.S.R. 376(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C.O.209”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES)

No. 5 ORDER, 2005

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2005.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010, shall be twenty-nine and one-half per cent., which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.356
Arunachal Pradesh	0.288
Assam	3.235
Bihar	11.028
Chhattisgarh	2.654
Goa	0.259
Gujarat	3.569
Haryana	1.075
Himachal Pradesh	0.522
Jammu and Kashmir	1.297
Jharkhand	3.361
Karnataka	4.459
Kerala	2.665
Madhya Pradesh	6.711
Maharashtra	4.997
Manipur	0.362
Meghalaya	0.371
Mizoram	0.239
Nagaland	0.263
Orissa	5.161
Punjab	1.299
Rajasthan	5.609
Sikkim	0.227
Tamil Nadu	5.305
Tripura	0.428
Uttar Pradesh	19.264
Uttaranchal	0.939
West Bengal	7.057

(2) The twenty-nine and one-half per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.453
Arunachal Pradesh	0.292
Assam	3.277
Bihar	11.173
Chhattisgarh	2.689
Goa	0.262
Gujarat	3.616
Haryana	1.089
Himachal Pradesh	0.529
Jharkhand	3.405
Karnataka	4.518
Kerala	2.700
Madhya Pradesh	6.799
Maharashtra	5.063
Manipur	0.367
Meghalaya	0.376
Mizoram	0.242
Nagaland	0.266
Orissa	5.229
Punjab	1.316
Rajasthan	5.683
Sikkim	0.230
Tamil Nadu	5.374
Tripura	0.433
Uttar Pradesh	19.517
Uttaranchal	0.952
West Bengal	7.150

Provided that where in any year the service tax become leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. One per cent. of the net proceeds of taxes and duties other than service tax, referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2005 but ending before the 1st day of April, 2010 but not later than the date with effect from which tax rental arrangement under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) is terminated shall be distributed among the States as follows:—

State	Percentage
(1)	(2)
Goa	0.262
Gujarat	3.616
Haryana	1.089
Himachal Pradesh	0.529
Jharkhand	3.405
Karnataka	4.518
Kerala	2.700
Madhya Pradesh	6.799
Maharashtra	5.063
Manipur	0.367
Meghalaya	0.376
Mizoram	0.242
Nagaland	0.266
Orissa	5.229
Punjab	1.316
Rajasthan	5.683
Sikkim	0.230
Tamil Nadu	5.374
Tripura	0.433
Uttar Pradesh	19.517
Uttaranchal	0.952
West Bengal	7.150

Provided that no share shall be payable to a State in a year where that State levies any tax or duty on the sale or purchase of any of the goods described in column (3) of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957):

Provided further that where in any year the service tax become leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the State of Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to paragraph 4.

6. If in any year during the period 2005-2010, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

7. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2000, shall, as from the 1st day of April, 2005, stand repealed.

8. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

A. P. J. ABDUL KALAM,
President.

[F. No. 19(6)/2005-L.I.]
T. K. VISWANATHAN, Secy.

1740 E/105-3